4 साल में विकास की कोई भी योजना नहीं हुई सफल

जितनी भी योजनाएं बनीं, वह ग्राउंड पर जीरो साबित

पुनीत दुबे

इटारसी, 10 मई, इटारसी के विकास की बड़ी योजनाओं पर ग्रहण लग गया है. नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने 26 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किया था, तब शहरवासियों को लगा था कि पुराने सभी अध्यक्षों का रिकॉर्ड तोड़कर विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे.

लेकिन जितनी भी बड़ी योजनाएं बनी वह ग्राउंड पर जाकर जीरो साबित हो गई है. इन सभी योजनाओं का विफल होना तकनीकी विभाग और प्रशासनिक पर पकड़ न होना साबित करता है. शहर के बैल बाजार स्थित भूमि पर बनने वाली योजनाओं में भूमिपूजन का रिकॉर्ड ही टूट गया. यदि पिछली कुछ घटनाओं को याद करते तो नगर पालिका परिषद इटारसी ने मुख्य बाजार क्षेत्र में रेस्ट हाउस के सामने (पुत्री शाला स्कूल परिसर में बने शिक्षक सदन के सामने आकांक्षी शौचालय (एस्पिरेशनल टॉयलेट) बनाने का साहस पुन: किया. पहले भी नपा के एक ठेकेदार ने उक्त स्थान पर 5 दुकानों का निर्माण कर लिया था, जिस ठेकेदार को जांच एजेंसी भी नहीं ढूंढ पायी थी. क्योंकि मामला दुकान निर्माण का था. इसलिये भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपस में दुकान बांटकर तीन शिक्षकों की पेंशन और वेतन वृद्धि को रुकवा दिया था. आज उक्त शिक्षकों के परिवार अपनी दुखभरी गाथा को लेकर जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा. एक शिक्षक अजय दुबे का तो निधन हो गया.

अन्य दो शिक्षक जिसमें से सुधांशु शेखर मिश्रा सेवानिवृत्त हो चुके हैं बताया जाता है कि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभी इसकी कोई अनुमति नहीं दी है. दावा किया जा रहा है कि 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस टॉयलेट में तमाम तरह की सुविधा होंगी और इससे शहर के व्यापारियों को फायदा होगा. जानकारी के मुताबिक नगर पालिका जिस स्थान पर यह महत्वाकांक्षी टॉयलेट बनाने जा रही है, यह जमीन शिक्षा विभाग की है और शिक्षक सदन का हिस्सा है. उनका सवाल था कि क्या शिक्षा विभाग ने यह भूखंड नपा को ट्रांसफर कर दिया है किंतु इस पर किसी भी निर्माण की इजाजत नहीं दी है. करीब 10 साल पहले शिक्षा विभाग के इस शिक्षक सदन से जुड़े इस स्थान पर कुछ दुकानों का निर्माण किया गया था. उसमें एक पूर्व पार्षद का नाम खुलेआम लोग ले रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ. ये तीनों शिक्षकों के निलंबित होने के बाद दो की वेतनवृद्धि और एक शिक्षक की पेंशन 50 प्रतिशत रोककर प्रशासन ने स्वयं को तो बचा लिया था लेकिन इन तीनों शिक्षकों को बगैर किसी दोष के दोषी बता दिया था और इन तीनों को इसकी सजा भी भुगतनी पड़ी. शिक्षक सदन में तीनों निर्दोष शिक्षकों पर हुई प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी व अन्य विभाग से नपा प्रशासन को अनुमति मिलने की आस में योजना बना ली थी, जिसके टेंडर भी हो गये थे और चहेते ठेकेदार को ठेका भी मिल गया था. पर भला हो अधिकारियों का जिन्होंने कहा कि कोई अनुमति नहीं देते. नगरपालिका द्वारा अनुमति नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग की जमीन पर एस्पिरेशनल टॉयलेट बनाने की योजना बंद करनी पडी.

योजनाएं जो धरातल पर नहीं आ सकीं

- नल जल योजना
- बीओटी काम्पलेक्स
- पुरानी इटारसी स्थित बस स्टेंड
- चौपाटी बाजार
- कान्वेंट स्कूल के बाजू में स्थित न्यास दुकानों की नीलामी
- थाने के बाजू में स्थित कॉम्पलेक्स
- शहर के सभी वाचनालय बंद
- शिक्षक सदन में एस्पिरेशनल टॉयलेट की परमीशन नहीं मिल पाना

हमने प्रशासन से शहर के विकास के अंतर्गत नागरिकों की जनसुविधा के लिये अनेक योजनाएं वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जा चुकी है लेकिन वहां से स्वीकृति प्रदान होते ही कार्य शुरू कर दिया जावेगा.

पंकज चौरे,
अध्यक्ष नपा परिषद इटारसी

आज कूनो में दो मादा चीतों को करेंगे मुक्त

- कार्यक्रम 'प्रोजेक्ट चीता' को मिलेगी नई गति
- बोत्सवाना से लाए चीतों ने पूरा किया क्वारंटीन

भोपाल 10 मई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 मई सोमवार को श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े से दो मादा चीतों को सुबह कूनो नदी के समीप स्थित साइट से खुले जंगल में मुक्त करेंगे. साथ ही कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दो चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने का यह कार्यक्रम 'प्रोजेक्ट चीता' को नई गति प्रदान करेगा और भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा. बोत्सवाना से लाए गए नौ चीतों ने अपनी क्वारंटीन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है. इसके बाद उन्हें छोटे बाड़ों में रखा गया था, ताकि वे स्वयं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाल सकें. अब इनमें से दो चीतों को पूर्णत: खुले जंगल में मुक्त किये जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है.

प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य प्रदेश से लुप्त हुये चीतों की प्रजाति को पुनर्स्थापित करना, उनकी संख्या में वृद्धि करना और उन्हें स्वतंत्र रूप से शिकार और विचरण के लिए तैयार करना है.

फरवरी में बोत्सवाना से आए थे 9 चीते

फरवरी 2026 के अंत में बोत्सवाना से 9 नए चीते कूनो नेशनल पार्क लाए गए थे. इनमें 6 मादा और 3 नर शामिल हैं. इन चीतों के आगमन के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या, देश में जन्मे शावकों सहित, बढ़कर 57 हो गई है. यह 'प्रोजेक्ट चीता' के अंतर्गत तीसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चरण है. नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीते भारत लाए गए थे, जबकि वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कूनो पहुंचे थे. बोत्सवाना से आए चीतों को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान के माध्यम से ग्वालियर लाया गया था.

भाजपा नेता और पत्रकार सहित छह लोगों के मोबाइल चोरी

बैतूल. शहर के सदर सब्जी बाजार में रविवार को जेबकतरों ने भाजपा नेता, पत्रकार सहित छह लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए. लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. बाजार में खरीदारी करने पहुंचे पत्रकार मयंक भार्गव, भाजपा नेता मनीष सिंह ठाकुर, अनूप वर्मा तथा रिचर्ड गोम्स सहित कुल छह लोगों के मोबाइल फोन भीड़भाड़ के दौरान अज्ञात चोरों ने पार कर दिए. पीड़ितों को घटना की जानकारी तब लगी, जब उन्होंने फोन निकालने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार मामले में पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं.

मध्यप्रदेश में मौसम का मिला-जुला मिजाज

कहीं बारिश तो कहीं भीषण गर्मी

भोपाल, 10 मई. प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं. प्रदेश के शहडोल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है. वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में भी बूदाबांदी दर्ज की गई है.

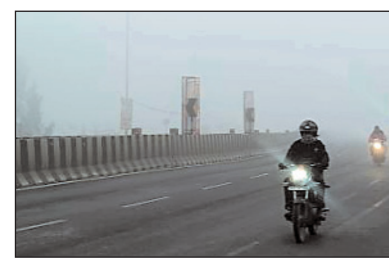

तो कई संभागों में मौसम शुष्क बना रहा तो कई जिलो में गर्मी की लू का सितम भी जारी हो गया है. तापमान की बात करें तो ग्वालियर रीवा जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में दिन का पारा सामान्य से काफी कम रहा, जबकि उज्जैन संभाग में यह सामान्य से अधिक दर्ज किया गया. वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रतलाम में 44.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. तो सबसे कम न्यूनतम तापमान कटनी के करौंदी में 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा. पचमढ़ी में सबसे कम अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा. जबकि राजगढ़ और अमरकंटक में भी रात का तापमान काफी कम दर्ज किया गया है. प्रदेश के कई हिस्सों जैसे सागर सीहोर और जबलपुर में तेज हवाएं और आंधी का असर भी देखा गया. बैतूल और राजगढ़ जिलों में ओलावृष्टि की सूचना भी मिली है.

भोपाल में मौसम...

मौसम रविवार को दिन में तेज धूप और लू जैसी तेज हवायें चली. जबकि शवनिवार रात में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई थी. जिसके बाद मौसम में कुछ हद तक ठंडक देखने को मिली थी. लेकिन रविवार के मौसम ने फिर से लोगों को गर्मी की लू से झुलसाये रखा. वहीं दिन शहर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा. हालांकि शाम होते होते मौसम में हल्का बदलाव नजर आया. फिलहालआने वाले दिनों में दिन में तपिश बढ़ सकती है.

10 लाख से अधिक किसानों से गेहूं उपार्जन

63 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुआ गेहूं उपार्जन

पंजाब के बाद सर्वाधिक गेहूं उपार्जन करेगा मप्र

भोपाल, 10 मई. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा प्रदेश में हो रहे गेहूँ उपार्जन की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है.

राज्य	विक्रेता किसान(लाख में)	अंतिम तारीख
मध्यप्रदेश	10	23.5.2026
हरियाणा	9.10	15.5.2026
पंजाब	7.5	10.5.2026
उत्तर प्रदेश	2	15.6.2026
राजस्थान	1.67	31.5.2026

वे स्वयं खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं. उन्होंने स्वयं तौल व्यवस्थाए बारदाने की उपलब्धता और खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये उपलब्ध जरूरी सुविधाओं का आकस्मिक निरीक्षण भी किया है. साथ ही किसानों से संवाद कर उपार्जित गेहूँ के भुगतान आदि के बारे में जानकारी ली जा रही है. मुख्यमंत्री के इन औचक निरीक्षण से उपार्जन केन्द्रों की व्यवस्थाएँ और अधिक अनुकूल और सहज हो रही हैं. मुख्यमंत्री डॉण् यादव के निर्देशानुसार मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है. देश में गेहूँ उपार्जन के मामले में मध्यप्रदेश अब लगातार आगे बढ़ रहा है. इस वर्ष पंजाब के बाद सर्वाधिक गेहूँ उपार्जन मध्यप्रदेश में होने जा रहा है. प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक किसानों से 63 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन किया जा चुका है. प्रतिदिन लगभग 5 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया जा रहा है. शनिवार 9 मई को ही 4 लाख 86 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन हुआ है.

एसपी भूटिया ने औचक निरीक्षण कर चार थानों की व्यवस्थाएं परखीं

शिवपुरी. नई पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भुटिया ने जिला मुख्यालय के चार प्रमुख थानों का औचक निरीक्षण किया. इनमें कोतवाली, देहात, फिजिकल और महिला थाना शामिल हैं. निरीक्षण के दौरान एसपी भुटिया ने थानों में चल रही कार्यवाहियों की जानकारी ली. उन्होंने परिसर, हवालात, रिकॉर्ड रूम और आर्म्स रूम का बारीकी से जायजा लिया और अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

15 से पुणे-गोरखपुर के बीच चलेगी ट्रेन

भोपाल, 10 मई. ग्रीष्मकाल के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पुणे-गोरखपुर-पुणे मार्ग पर विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. बता दें पुणे-गोरखपुर-पुणे स्पेशल ट्रेन 15 मई से 15 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन संचालित की जाएगी.

जि कि पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं पुणे से गोरखपुर यह ट्रेन 15 मई से 15 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 6 बजकर 50 बजे पुणे से रवाना होगी. उसी दिन रात 9 बजकर 10 बजे इटारसी और 11 बजकर 15 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी. जो कि अगले दिन मध्यरात्रि 1 बजकर 25 बजे बीना होते हुए 4 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वहीं गोरखपुर से हड़पसर वापसी में यह ट्रेन 16 मई से 16 जुलाई तक प्रतिदिन शाम 5 बजकर 30 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करेगी. अगले दिन सुबह 8 बजे बीना, 10 बजकर 30 बजे रानी कमलापति और दोपहर 12 बजकर 10 बजे इटारसी पहुंचेगी.

तीसरे दिन सुबह 3 बजकर 15 बजे यह ट्रेन हड़पसर पहुंचेगी. बता दें ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिये कुल 18 कोच होंगें. वहीं ट्रेन अपने मार्ग में दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी.

हथियार नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 10 मई. मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशभर में अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के खिलाफ व्यापक अभियान तेज करते हुए पिछले दस दिनों में 29 अवैध हथियार, कारतूस तथा हथियार निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण जब्त किए हैं.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध हथियारों के संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की जा रही है. छतरपुर जिले में कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण एवं सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दो अवैध हथियार निर्माण इकाइयों का भंडाफोड़ कर एक देशी बंदूक, सात देशी कट्टे, एक अधबनी पिस्टल, एक अधबना कट्टा, जिंदा कारतूस और खाली खोखे बरामद किए.

17 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की

इसके अलावा हथियार निर्माण में प्रयुक्त मशीनें, उपकरण और अन्य सामग्री भी जब्त की गई. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. टीकमगढ़ जिले में विशेष अभियान के तहत पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 17 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छह देशी कट्टे, आठ जिंदा कारतूस और 11 धारदार हथियार जब्त किए. ग्वालियर पुलिस ने भी अलग-अलग अभियानों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया.

ओबीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन को मिला समर्थन

पटवारी ने आंदोलनरत युवाओं से मुलाकात की

विशेष संवाददाता

भोपाल, 10 मई. मध्यप्रदेश में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में 13 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े पदों को होल्ड रखने के विरोध में आंदोलन कर रहे ओबीसी अभ्यर्थियों को रविवार को कांग्रेस का समर्थन मिला.

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल स्थित आंबेडकर पार्क पहुंचकर आंदोलनरत युवाओं से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया. प्रदेशभर से आए अभ्यर्थी 13 प्रतिशत होल्ड अभ्यर्थी संघ के बैनर तले शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में रोके गए पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाएं अधर में लटकी हुई हैं, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

गौरतलब है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है. इसी कारण सरकार ने कई भर्ती प्रक्रियाओं में 13 प्रतिशत पदों को होल्ड कर रखा है. इसका असर वर्ष 2018, 2020 और 2023 की विभिन्न परीक्षाओं एवं नियुक्तियों पर पड़ा है. धरना स्थल पर संबोधित करते हुए पटवारी ने भाजपा सरकार पर सामाजिक न्याय और आरक्षण की भावना को कमजोर करने का आरोप लगाया.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अदालत में मामले की गंभीरता से पैरवी नहीं की और बार-बार वकीलों के पैनल बदलने से स्थिति और जटिल हो गई. पटवारी ने आरक्षण कानून को लेकर मुख्यमंत्री की हालिया टिप्पणियों की भी आलोचना करते हुए उन्हें संविधान और ओबीसी समाज का अपमान बताया. उन्होंने मांग की कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ तत्काल बहाल किया जाए और होल्ड पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएं.

चिंता — नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद दिखीं प्रशासनिक विफलताएं : अजय

शिक्षा व्यवस्था पर विपक्ष का हमला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 10 मई. पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इससे शिक्षा क्षेत्र में गहरी प्रशासनिक विफलताएं उजागर हुई हैं.

अजय सिंह ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट ने सरकारी दावों और प्रदेश के सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति के बीच की खाई को सामने ला दिया है. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की बात करने वाले दौर में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की यह स्थिति बेहद शर्मनाक है.

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 13,500 से अधिक स्कूल आज भी बिना बिजली के संचालित हो रहे हैं, जिससे कक्षाएं अंधेरे में चल रही हैं और पढ़ाई की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है. उन्होंने छात्राओं के लिए शौचालयों की कमी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि करीब दो हजार स्कूलों में अलग शौचालय नहीं हैं, जो महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के दावों पर सवाल खड़े करता है. कांग्रेस नेता ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा भी उठाया. उनके अनुसार प्रदेश में 52 हजार से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिनमें 45 हजार से ज्यादा पद प्राथमिक स्कूलों के हैं. वहीं सात हजार से अधिक स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं.

उन्होंने प्रदेश के लगभग 40 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा नहीं होने पर भी सरकार को घेरा और कहा कि शिक्षा सुधारों के प्रचार के बावजूद राज्य आधुनिक शिक्षा मानकों से पीछे होता जा रहा है. शिक्षा बजट के उपयोग पर सवाल उठाते हुए सिंह ने कहा कि बुनियादी ढांचे की कमजोरी के कारण लगभग 3.37 लाख बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा बीच में ही छोड़ दी. उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर करीब 17 प्रतिशत ड्रॉपआउट दर यह दर्शाती है कि सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़कर रखने में विफल रही है.

जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी, खाली पड़े केबीन

बड़वानी. जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान हैं। शुक्रवार को हमारी टीम ने ओपीडी का वास्तविक स्थिति (रियलिटी चेक) किया तो बदहाली सामने आई। शिशु रोग विशेषज्ञ के तीन केबिन में से दो खाली मिले। सिर्फ एक केबिन में डॉ नागौर मौजूद थे। मेन ओपीडी में मेडिसिन विशेषज्ञ भी नदारद थे। डॉक्टरों के नहीं होने से मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ा। कई सरकारी डॉक्टर ड्यूटी समय में निजी क्लीनिक पर बैठते हैं। इस कारण ओपीडी में अक्सर नहीं आते। सरकारी वेतन तो लेते हैं, लेकिन इलाज अपने निजी क्लीनिक पर करते हैं. मजबूरी में मरीजों को पैसा देकर निजी क्लीनिक पर इलाज कराना पड़ता है.

फर्जी अवैध अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा

- खंगाले जाएंगे पंजीयन और डिग्री

उज्जैन. शहर में गली-मोहल्लों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और पॉली क्लीनिकों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. वर्षों से चंद रुपयों के लालच में बिना पर्याप्त संसाधनों, बिना पंजीयन और बिना योग्य चिकित्सकों के अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं.

इन अस्पतालों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, बोतलें चढ़ाई जा रही हैं, छोटे-बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं, यहां तक कि आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर भी संचालित किए जा रहे हैं, कई अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहद कमजोर, इलाज गुणवत्ताहीन किए जा रहे. जांच दल यह देखेंगे कि अस्पताल में मान्यता प्राप्त डॉक्टर कार्यरत हैं या नहीं, उनके पास वैध डिग्रियां हैं या नहीं, प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है या नहीं, अस्पताल का सीएमएचओ कार्यालय में विधिवत पंजीयन है या नहीं, तथा आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और अन्य उपकरण तकनीकी रूप से सक्षम और कार्यशील हैं या नहीं. यह भी जांचा जाएगा कि मरीजों का किस बीमारी के लिए उपचार किया जा रहा है.

उज्जैन शहर के लिए 5 जांच दल गठित

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने मोर्चा खोल दिया है. कलेक्टर ने अपंजीकृत क्लीनिकों और अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उनके आदेश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार पटेल ने शहर और जिले में संचालित अस्पतालों एवं क्लीनिकों की जांच के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है(कलेक्टर के निर्देश पर उज्जैन शहर में संचालित क्लीनिकों और अस्पतालों के निरीक्षण के लिए पांच जांच दल गठित किए गए हैं. ये दल अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर अस्पतालों, क्लीनिकों और पॉलीक्लिनिकों का निरीक्षण करेंगे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे. इसके साथ ही जिले के सभी ब्लॉक मेडिकल अधिकारियों और मेडिकल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करें और अवैध रूप से संचालित अपंजीकृत अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें. वैध रूप से पंजीकृत अस्पतालों की भी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हो रहे हैं.